रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2000/भाद्र 6, 1922
No. 118] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2000/BHADRA 6, 1922

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2000

सं. 301-8/2000-टीआरएआई (इकॉन).— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप धारा (2) के अंतर्गत स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत से बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है ।

दूरसंचार टैरिफ (नवां संशोधन) आदेश 2000
(2000 का क्रमांक 3)

भाग-1

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (नवां संशोधन) आदेश, 2000" के नाम से जाना जाएगा ।

2337 GI/2000

(ii) यह आदेश 1 अक्टूबर, 2000 से लागू होगा ।

भाग-II

टैरिफ

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची 1, (आई एस डी एन को छोड़कर) बुनियादी या आधारभूत सेवाओं में, क्रम संख्या (5) और (6) की मदों के निमित्त, 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किराए, उनमें उल्लिखित तारीखों के बावजूद, 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि के लिए भी लागू बने रहेंगे ।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची 1, (आई एस डी एन को छोड़कर) बुनियादी या आधारभूत सेवाओं में, क्रम संख्या 12 की मद के निमित्त, 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफ/ पल्स रेट / प्रभार का कार्यान्वयन, उसमें उल्लिखित तारीखों के बावजूद, 1 अक्टूबर 2000 से 31 मार्च, 2002 तक लागू होगा ।

भाग III

व्याख्यात्मक ज्ञापन

4. इस आदेश के अनुलग्नक "क" में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है।

आदेशानुसार

डा० हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[विज्ञापन/3/4/असा०/161/2000]

अनुलग्नक "क"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (टी टी ओ 99") का, बुनियादी सेवाओं से संबंधित एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि टैरिफों का पुन: संतुलन ऐसा हो ताकि किरायों में वृद्धि हो तो लंबी दूरी के, याने एस टी डी और आई एस डी के, काल प्रभारों में कमी होती जाय । यह पुन: संतुलन तीन कालावधियों में कार्यान्वित होना था । पहली कालावधि मई 1999 में कार्यान्वित हुई । प्राधिकरण ने मार्च 1999 के अपने आदेश में, टैरिफ पुन:संतुलन में निहित राजस्व घटकों का आकलन, टी टी ओ 99 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 63 (सारणी 9) में किया था । यह अनुमान लगाया गया था कि टैरिफ पुन:संतुलन की प्रथम कालावधि के परिणाम स्वरूप, वर्तमान पदधारी प्रचालकों याने आपरेटरों को समग्र रूप से अतिरिक्त राजस्व (233 करोड़ रूपए से अधिक) की प्राप्ति होगी । व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 12 और 73 में, प्राधिकरण ने इस बात को भी माना था कि पदधारी की राजस्व विवक्षाओं (इंप्लीकेशंस) पर प्राधिकरण अपने आकलनों के साथ, वास्तविक राजस्वों की तुलना करेगा और पहले साल के आखिर में, यदि वास्तविक स्थिति काफी भिन्न होगी तो वह सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ।

2. टी टी ओ 99 की अधिसूचना के बाद, और मार्च 1999 में नई दूर-संचार नीति (एन टी पी), 1999 की घोषणा के फलस्वरूप, दूरसंचार विभाग के सचिव ने टी आर ए आई को पत्र लिखा, इसमें, अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया कि :

"टी आर ए आई द्वारा 9 मार्च के टैरिफ आदेश के बाद, बीते कल नई दूरसंचार नीति की घोषणा से बड़े महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं जिनसे समग्र दूरसंचार सेक्टर की अर्थव्यवस्था का ढाँचा ही काफी बदलने सा लगा है। नई नीति में, मात्र एक बार के प्रवेश शुल्क सहित राजस्व भागीदारी व्यवस्था की बात कही गई है। नीति में यह भी उल्लेख है कि सरकार उपरोक्त मुद्दे पर टी आर ए आई की सिफारिशें माँगेगी। इसलिए टैरिफ की दरों के निर्धारण की गणनाएं, और इनके लिए अपनाए गए रीतिविधान, इन परिवर्तनों के मद्देनजर बहुत बदल जाएंगे। इसलिए, पहले साल के वास्ते 9 मार्च 1999 के टैरिफ आदेश का कार्यान्वयन करने के साथ-साथ, टी आर ए आई को आगे की अवधि के लिए, परिवर्तनों को ध्यान में रखकर, टैरिफ की दरों पर दुबारा काम करना चाहिए ताकि नई दरों, और सरकार की नई दूरसंचार नीति के बीच तालमेल तथा सुसंगतता हो।"

3. अतः, टी टी ओ "99 में परिकल्पित स्थिति से, वास्तविक स्थिति काफी भिन्न हो जाने के कारण और टीटीओ "99 की घोषणा के बाद सरकार द्वारा नई नीति, याने एन टी पी "99 के ऐलान के कारण, प्राधिकरण द्वारा समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया था। एन टी पी "99 में, देश के लिए बहुत महत्त्वाकांक्षी दूरसंचार घनत्व अर्थात टेलीडेन्सिटी के लक्ष्य रखे गए हैं। यह सन् 2010 तक 15 प्रतिशत का है। इसमें ग्रामीण टेलीडेन्सिटी का लक्ष्य भी सन् 2010 तक, 0.4 से 4 (प्रतिशत) का रखा गया है। इससे इस बात का दुबारा आकलन जरूरी हो गया है कि टैरिफ संरचना का लोगों की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप माँग और दूरसंचार घनत्व पर, खासतौर पर ग्रामीण दूरसंचार घनत्व पर क्या असर होगा जिसे सन् 2010 तक 4 प्रतिशत हो जाना है।

4. दूरसंचार टैरिफ आदेश (टी टी ओ) "99 में, मानक टैरिफ पैकेज विनिर्दिष्ट किए गए थे और सेवा प्रदाताओं को यह छूट दी गई थी कि वे मानक टैरिफ पैकेज के साथ-साथ वैकल्पिक टैरिफ पैकेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

डी टी एस ﴾और एम टी एन एल﴿ ने एक वैकल्पिक टैरिफ पैकेज प्रस्तुत किया । इसके अंतर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए किरायों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और शहरी उपभोक्ताओं के लिए यह 200 मीटर्ड काल यूनिट ﴾एम सी यू﴿ प्रति माह रखा गया । इसके साथ साथ, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नि:शुल्क कालों की संख्या में कोई कटौती नहीं थी । इस नीति से, कम कॉल करने वालों के लिए, टैरिफों की सह्यता या सामर्थ्य में तो सुधार हुआ पर इससे यह भी हुआ कि राजस्व उससे कम मिले जो मानक टैरिफ पैकेज लागू हो जाने पर मिल जाते । यह अनुमान है कि इसमें लगभग 1,100 से 1,200 करोड़ रूपए तक राजस्व, उस राजस्व राशि से कम बैठा जो तब प्राप्त होता अगर 1999-2000 में मानक टैरिफ पैकेज कार्यान्वित हो गया होता ।

5. मानक टैरिफ पैकेज में यह परिकल्पना थी कि, टैरिफों के पुन: संतुलन के निमित्त, और बुनियादी या आधारभूत सेवाओं को और अधिक उन्मुक्त या खुला करने की जमीन तैयार करने के लिए, एस टी डी/आई एस डी काल प्रभारों में कमी और किरायों में बढ़ोत्तरी करनी होगी । एस टी डी/आई एस डी काल प्रभारों में, और किरायों में अपेक्षित परिवर्तन, एकमुश्त या एक साथ करना, बहुत तीव्र और तीक्ष्ण माना गया और इसलिए इसके लिए तीन कालावधियां निर्दिष्ट की गईं । टैरिफ परिवर्तन का अधिकांश भाग पहली दो कालावधियों में ही हो जाना था । पहली कालावधि 1 अप्रैल 2000 से कार्यान्वित होना था ।

6. प्रथम कालावधि समाप्त हो रही थी कि दूरसंचार सेवा विभाग ﴾डी टी एस﴿ ने प्राधिकरण को प्रतिवेदन दिया कि टैरिफ परिवर्तनों से उनके राजस्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अपने 8 मार्च 2000 के पत्र में, डी टी एस ने टी आर ए आई को बताया कि वित्तीय वर्ष 1999/2000 के दौरान, "डी टी एस के राजस्वों में निवल प्रतिकूल प्रभाव लगभग

2000-2200 करोड़ रुपए की सीमा तक हो सकता है ।" अतः डी टी एस ने प्राधिकरण से टी टी ओ "99 की समीक्षा का अनुरोध किया जिसके अनुसार । अप्रैल 2000 से दीर्घदूरिक या लंबी दूरी के प्रभारों में और अधिक कमी हो जानी है । उनके अनुसार यह इसलिए जरूरी है कि डी टी एस को राजस्व का और ज्यादा नुकसान न हो ताकि वह अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए पैसा जुटा सके - खास तौर पर घाटे वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि टेलीडेन्सिटी को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं ।

7. प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि टी टी ओ "99 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 12 और 73 में दी गई व्यवस्था के अनुसार, वह टैरिफ पुनः संतुलन कार्यों की समीक्षा करेगा ।

8. समीक्षा करने की दृष्टि से, परिवर्तनों की दूसरी कालावधि के कार्यान्वयन को चार महीना स्थगित किया गया । इस अवधि को फिर एक महीना आगे स्थगित किया गया क्योंकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने अपने आंकड़े करीब करीब चार महीने के आखिरी दौर में ही दिए । इससे प्राधिकरण को उपयुक्त विश्लेषण के लिए समय नहीं मिला । सेवा प्रदाताओं से आंकड़े और सूचना आदि मिल जाने के बाद, टी आर ए आई ने टैरिफ समीक्षा का काम पूरा कर लिया है । "डी ई एल" और "एम सी यू" की बढ़ोत्तरी अथवा वृद्धि के संदर्भ में, समीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को, नीचे क्रम संख्या । व 2 सारणियों में सारांश रूप से दिखाए गया है :

सारणी 1· 1999-2000 के दौरान, "एम सी यू" और "डी ई एल" में प्रतिशत वृद्धि

टीटी ओ, 1999 में परिकल्पित		वास्तविक वृद्धि		
		डीटीएस	एमटीएनएल	डीटीएस और एमटीएनएल
एमसीयू	12·9%	10·95%	7·37%	10·2% (अंतिम छः महीनों में 12 %)
डी ई एल	18%	25·36%	7·82%	22%

स्रोत : दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) - दिनांक 31 मई, 1 व 3 अगस्त, 2000 के पत्र

9· ऊपर की सारणी 1 से स्पष्ट है कि, प्रमुख पदधारी (सेवा-प्रदाता) - डी टी एस ने, डी ई एल में, टी टी ओ "99 के अनुसार परिकल्पित औसत प्रतिशतता वृद्धि प्राप्त कर ली । और "एम सी यू" में उसने उससे थोड़ी कम बढ़ोत्तरी प्राप्त की जो टी टी ओ "99 में सोची गई थी । डी टी एस और एम टी एन एल को साथ रखने पर, उनका औसत भी इसी तस्वीर के मुताबिक है । साल के अंतिम छः महीनों की "एम सी यू" वृद्धि की दर से ऐसा लगता है कि, कीमतें घटा देने पर एस टी डी के परिणाम या प्रतिक्रिया, टैरिफ पुनः संतुलन के पहले साल के मुकाबले दूसरे साल ज्यादा प्रबल होते हैं ; वित्तीय वर्ष के अंतिम चार महीनों के दौरान एम सी यू में वृद्धि 13·2 प्रतिशत रही । इससे

संकेत मिलता है कि अपने बढ़ हुए समय, याने 31 मार्च 2000 के बाद के समय को मिलाकर टैरिफ परिवर्तन की प्रथम कालावधि में समग्र रूप से और जैसा परिकल्पित था, डी ई एल और एम सी यू के स्तर पर कार्यनिष्पादन लगभग वैसा ही रहा जैसा टी टी ओ "99 में सोचा गया था । इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि, हालांकि "डी ई एल" और "एम सी यू" में कुल वृद्धि लगभग उतनी ही रही जितनी "टी टी ओ "99 में परिकल्पित थी तथापि अंतर्राष्ट्रीय काल "एम सी यू" में वृद्धि आशा से बहुत कम थी भले ही हम वित्तीय वर्ष के दूसरे आधे को ही ध्यान में रखें ।

10. "डी ई एल" और "एम सी यू" की वृद्धि आकलन के अनुरूप होने के बावजूद, राजस्व आशा से कम संभव है क्योंकि एक तो मानक टैरिफ पैकेज कार्यान्वित नहीं किया गया और दूसरे, प्रतिकाल प्रभार प्रत्याशित से कहीं अधिक नीचे आ गया । राजस्व की स्थिति की समीक्षा, टी आर ए आई द्वारा उस सूचना को आधार मानकर की गई जो उसे सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई । इस काम में उसी रीति विधान या तरीकों को अपनाया गया जो डी ओ टी ने समीक्षा के लिए, मार्च 2000 में टी आर ए आई से अनुरोध करते समय, राजस्व कमी के प्राक्कलन हेतु अपनाए थे । उस समय उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, डी टी एस ने लगभग 2,150 करोड़ रुपए के किराए और काल राजस्व की कमी का अनुमान लगाया था ।

11. टी आर ए आई की गणनाएँ अधिक नवीन आंकड़ों पर आधारित हैं । इसे नीचे सारणी 2 में दिखाया गया है ।

सारणी 2

डी टी एस और एम टी एन एल के, 1998-99 एवं 1999-2000 की अवधि में, मीटर्ड काल यूनिट (एम सी यू), काल राजस्व प्रति मीटर्ड काल यूनिट पर औसत प्रभार तथा किराया राजस्व

	दूरसंचार सेवा विभाग (डी टी एस)		महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम टी एन एल)	
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
एम सी यू (करोड़)	11,390	12,637·8	3,374	3,638
काल राजस्व (करोड़ रुपए)	11,180	12,280	3,703·7	3,717
प्रति एम सी यू औसत प्रभार (रुपए)	0·98	0·97	1·1	1·02
किराया राजस्व (करोड़ रुपए)	2,643	3505 *	887	920 *

स्रोत : दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) (31 मई, 1 व 3 अगस्त, 2000 के पत्र)

* इसमें वर्ष 1999-2000 से संबंधित किरायों की राशियों के टी आर ए आई के प्राक्कलन शामिल हैं । इन राशियों को 1998-99 में एकत्र किया गया था और ये उस वर्ष के लेखों में क्रेडिट पर दर्शायी गई हैं ।

2337GI/2000-2

12. टी टी ओ '99 को अंतिम रूप दिए जाने से पहले, डी ओ टी ने काल और किराये के राजस्वों के बारे में डी ओ टी/एम टी एन एल के आकलित और प्रत्याशित आंकड़े दिए थे। ये प्रस्तावित टैरिफ पुन: संतुलन को गणना में रखे बगैर तैयार किए गए थे। 1999-2000 के लिए डी ओ टी ने इनका आकलन 23,253 करोड़ रुपए किया था। इन आंकड़ों का आधार 1.243 रु० प्रति प्रभार्य काल का प्रभार था। यह दर 1997-98 के हिसाब से बैठती थी। डी ओ टी को उम्मीद थी कि यही दर आगे भी मिलेगी यदि पुन: संतुलन की बात न आती। प्रत्याशित राशि, किंचित समायोजन के बाद, टी आर ए आई द्वारा 23,181 करोड़ रुपए रखी गई थी जैसा टी टी ओ 99 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में बताया गया है। टी आर ए आई ने 1999-2000 के राजस्वों के बारे में कुछ अपने आकलन भी किए जिनमें टैरिफ पुन: संतुलन के उसके प्रस्तावों में परिकल्पित विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया था, यह मानकर कि टैरिफ घटने की वजह से, एस टी डी/आई एस डी परियात [ट्रैफिक] में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है उसने 1999-2000 वर्ष के लिए 23,414 करोड़ रुपए राजस्वों का अनुमान लगाया। टी आर ए आई के विचार से टैरिफ पुन: संतुलन के पहले साल ऐसी स्थिति की संभावना बहुत अधिक थी। यह अनुमान डी ओ टी द्वारा उपलब्ध कराए गए उन आंकड़ों पर आधारित था जो उसने प्रति प्रभार्य काल पर, औसत प्रभार के बारे में, निकाले थे और जो 1999-2000 में टैरिफ पुन: संतुलन के परिणामस्वरूप प्राप्त हो सकते थे। वर्तमान समीक्षा के समय, 1998-99 वर्ष [या टैरिफ पुन: संतुलन से ठीक पहले के वर्ष] के वास्तविक काल प्रभार उपलब्ध करा दिए गए। यह लगभग 1.12 रुपए प्रति प्रभार्य काल बैठा। यह उस काल प्रभार से कम है जिसके आधार पर 23,414 करोड़ रुपए के पिछले प्राक्कलन आए थे। इसलिए 1998-99 में विद्यमान, उस कम और वास्तविक, काल-प्रभार के आधार पर राजस्व का संशोधित प्राक्कलन किया गया। यह

संशोधित प्राक्कलन 21,870 करोड़ रुपए बैठता है। राजस्व में कोई भी कमी इस आधार पर आंकनी होगी। इसकी तुलना में, 1999-2000 में वास्तविक अर्जित राजस्व 20,424 करोड़ रुपए निकला। फलस्वरूप लगभग 1,450 करोड़ रुपए की सकल कमी हो गई। इस राशि में राजस्व की वह हानि शामिल है जो टी टी ओ 99 द्वारा विनिर्दिष्ट मानक टैरिफ पैकेज का कार्यान्वयन न किए जाने की वजह से हुई। डी टी एस/एम टी एन एल को इस तरह हुई हानि लगभग 1,200 करोड़ रुपए अनुमानित है। अत: निष्कर्ष यह है कि 1999-2000 में राजस्व की वह हानि, जो तर्कसंगत रूप से टी टी ओ "99 के कारण हो सकती है, 250·00 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी।

13· उपर्युक्त लगभग 1,450 करोड़ रुपए की सकल राजस्व कमी में, वर्तमान पदधारी प्रचालकों याने डी टी एस और एम टी एन एल के हिस्से क्रमश: 600·00 करोड़ रुपए और 850·00 करोड़ रुपए हैं। जैसा पहले बताया जा चुका है, राजस्व में इस कमी का बड़ा भाग, मानक टैरिफ पैकेज लागू न किए जाने की वजह से है।

14· उपर्युक्त राजस्व अनुमानों को, दूरसंचार उपस्करों की घटती लागतों के साथ साथ देखना आवश्यक है। टी टी ओ "99 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 70-71 में जैसा उल्लिखित है, यह एक ऐसा घटक है जिसपर प्राधिकरण ने, टैरिफ पुन:संतुलन के राजस्व-प्रभाव पर निर्णय करते समय, विचार किया था। यह पहलू, और टैरिफ पुन:संतुलन की प्रथम कालावधि के निमित्त सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध अधिक समय, इस निष्कर्ष की ओर ले जाते है कि टैरिफ पुन:संतुलन की प्रथम कालावधि का, प्रचालकों के राजस्व पर प्रभाव, बहुत गंभीर नहीं कहा जा सकता। एक अन्य ध्यान देने वाली बात यह है कि, प्राधिकरण को आशा थी कि टैरिफ पुन:संतुलन के दौरान

हुई राजस्व कमी को बराबर, या निष्प्रभाव करने के लिए, दक्षता एवं कार्यकुशलता में सुधार लाया जाएगा । इन सब बातों के आधार पर, प्राधिकरण का मानना है कि, लंबी दूरी के काल राजस्व में ह्रास या कमी इतनी गंभीर व अधिक नहीं है कि, टी टी ओ "99 में परिकल्पित एस टी डी/आई एस डी काल प्रभारों को कम करने की दूसरी कालावधि को, और आगे स्थगित किया जाए ।

15• अतः, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि दूसरी कालावधि के लिए, एस टी डी/आई एस डी दरों में प्रस्तावित कमी 1 अक्टूबर 2000 से शुरू कर दी जाए । प्राधिकरण के विचार से, सेवा प्रदाताओं को इसकी तैयारी के लिए चार सप्ताह अपेक्षित होंगे ताकि वे सभी संबंधित एक्सचेंजों में परिवर्तनों को लागू कर सकें, और टैरिफ परिवर्तनों को ठीक तरीके से ले आने के निमित्त अन्य प्रबंध भी कर सकें ।

16• इसके साथ-साथ, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि एस टी डी/आई एस डी टैरिफों की दूसरी कालावधि 31 मार्च 2002 तक जारी रहेगी । अतः, समग्र रूप से पूरे टी टी ओ "99 का कार्यान्वयन तीन वर्ष के दौरान याने 1-4-99 से 31-3-2002 तक चलेगा ।

17• टैरिफ में कमी की दूसरी कालावधि के लिए अधिक लंबा समय इसलिए रखा गया है ताकि, दूरसंचार सेक्टर में, हाल के नीतिगत परिवर्तनों के प्रभावों से, बाजार का तालमेल बैठ जाए । साथ ही, दूसरी कालावधि के कार्यान्वयन को एक साल के बदले डेढ़ साल का समय देने से, माँग के लचीलेपन को वास्तविक स्वरूप में आने के लिए, ज्यादा अवधि मिल जाएगी । इससे पदधारी या सेवा प्रदाताओं को नए वातावरण के अनुरूप संरचनात्मक तालमेल बिठाने के लिए, कुछ अतिरिक्त समय मिल सकेगा क्योंकि दूरसंचार सेवा के बाजार में, सभी अवयवों में प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है ।

18. तीसरी कालावधि में, एस टी डी टैरिफों में उस औसत से लगभग 11.5 प्रतिशत की कमी हो जाएगी जो 1999-2000 में इन टैरिफों का होगा । टी टी ओ "99 में एस टी डी टैरिफों में परिकल्पित कुल कमी का करीब 85 प्रतिशत पहली दो कालावधियों में ही प्राप्त हो जाएगा । प्राधिकरण ने सरकार के उस निर्णय को नोट किया है जिसके अनुसार, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) के बाजार को मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है । प्राधिकरण को आशा है कि "एन एल डी" बाजार में निजी सेक्टर के प्रवेश से जो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी उससे एस टी डी की दरें खुद-ब-खुद काफी कम हो जाएंगी । प्राधिकरण का इरादा इस बदले हुए माहौल पर पूरी नज़र रखने का है । दूरसंचार विनियमन की नवीनतम प्रवृत्ति के अनुरूप, प्राधिकरण टैरिफ पुन: संतुलन के लिए, बाजार को ध्यान में रखते हुए, ऐसे तरीके अपनाएगा जिनमें बाजार और उसकी बढ़ोत्तरी पर, प्रतिस्पर्धा का प्रभाव शामिल होगा ।

19. टैरिफ परिवर्तन की दूसरी कालावधि में सामान्य उपयोग वाले अभिदाताओं के लिए किरायों में वृद्धि शामिल थी । ये ऐसे ग्राहक होते हैं जो बिलिंग साइकिल में 500 एम सी यू प्रतिमाह से ज्यादा काल करते हैं । प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि इन किरायों को न बढ़ाया जाए । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

(क) टैरिफ पुन: संतुलन की दूसरी कालावधि में परिकल्पित किराया वृद्धि से राजस्व की जो अतिरिक्त राशि मिलेगी, वह लगभग 200 करोड़ रुपए होगी । यह अगले साल के प्रत्याशित कुल राजस्व के 1 प्रतिशत से भी कम होगी । यह आशा की जा सकती है कि राजस्व के इतने घाटे को, पदधारी प्रचालक द्वारा, उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाकर, पूरा किया जा सकता है बल्कि इसे कुल नफे में बदला जा सकता है । साथ ही, चूंकि मांग, किराए या एक्सेस प्रभारों के प्रति संवेदनशील होती है उनके अनुसार घटती बढ़ती है, इसलिए प्राधिकरण उम्मीद करता है कि किराए न

बढ़ाए जाएं तो मांग तेजी से बढ़ेगी और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होंगे । टैरिफ पुन:संतुलन के दौरान, नीति के रूप में, प्राधिकरण इस बात को महत्त्व देता है कि, लागत और सहूयता या सामर्थ्य के बीच अच्छा संतुलन कायम रहे और टेलीफोनों की मांग ऐसे बढ़ती रहे कि, सन् 2010 तक 15 की टेलीडेन्सिटी का लक्ष्य भी सामने रहे और दूरसंचार सेवाओं में वित्तीय सक्षमता को भी संरक्षण मिलता रहे ।

(ख) प्राधिकरण ने, टैरिफ पुन:संतुलन की पहली और दूसरी, याने दोनों कालावधियों को अतिरिक्त समय दिया है । इससे अतिरिक्त राजस्व इतने प्राप्त हो सकते हैं कि वे, दूसरी कालावधि में किराए बढ़ाने पर प्राप्त हो सकने वाले राजस्वों से, कहीं अधिक बैठेंगे ।

(ग) उपस्करों की लागतें लगातार घट रही हैं । यदि नेटवर्क के, यातायात (ट्रैफिक) के प्रति, असंवेदी भाग की भावी लागतों को ही ध्यान में रखा जाए तो वह भी किरायों में वृद्धि न करने का अतिरिक्त आधार बन जाता है ।

(घ) टैरिफ की समीक्षा के दौरान, प्राधिकरण ने संशोधित रीतिविधान के आधार पर, लागत-आधारित टैरिफों पर दुबारा काम किया । इस प्रक्रिया का उल्लेख टी टी ओ 99 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 83 में है । यह रीतिविधान एवं नवीनतम अग्रतोमुखी लागत प्राक्कलन् निकट भविष्य में, परामर्श तथा विचारविमर्श के विषय होंगे । उसी में यह बात भी निहित होगी कि किराए और काल प्रभार के कतिपय आधारों की समीक्षा हो और उन पर दुबारा विचार किया जाए । इसलिए, जनवरी 2002 तक, किरायों में और वृद्धि न करना ही प्राधिकरण ठीक समझता है क्योंकि जनवरी 2002 में, लागत के आधार के साथ-साथ टैरिफ आदेश की समीक्षा भी होगी ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2000

No. 301-8/2000-TRAI (Econ.).— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

The Telecommunication Tariff (Ninth Amendment) Order 2000
(3 of 2000)

Section I

Title, Extent and Commencement

1 Short title, extent and commencement :

(i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (Ninth Amendment) Order 2000."

(ii) The Order shall come into force with effect from 1st October, 2000.

Section II

Tariff

2. For items (5) and (6) in Schedule I, Basic Services (other than ISDN) in the Telecommunication Tariff Order, 1999, notwithstanding the dates mentioned there-in, the rentals specified for the period 1st April, 1999 to 31st March, 2000 shall remain in operation also for the period 1st April, 2000 to 31st March, 2002.

3 For item (12) in Schedule I, Basic Services (other than ISDN) in the Telecommunication Tariff Order, 1999, notwithstanding the dates mentioned there-in, the implementation of tariffs/ pulse rates/ charges specified for the period 1st April, 2000 to 31st March, 2001 shall be operative from 1st October, 2000 to 31st March, 2002.

Section III

Explanatory Memorandum

4. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order

By Order

DR. HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser

[ADVT/III/IV/Exty./161/2000]

Annex A

Explanatory Memorandum

1. One of the main objectives of the Telecommunication Tariff Order, 1999 ("TTO '99") relating to basic services was to rebalance tariffs which envisaged an increase in rentals and a reduction in long distance call charges, i.e. for STD and ISD. The re-balancing was to be implemented in three phases. The first phase was implemented in May, 1999. The Authority in its Order of March, 1999 had worked out the revenue implications of the tariff re-balancing exercise at paragraph 63 (Table 9) of the Explanatory Memorandum to TTO '99. It was estimated that the first phase of the re-balancing exercise would result in overall positive revenue (plus Rs. 233 crores) for the incumbent operators. In paragraphs 12 and 73 of the Explanatory Memorandum, the Authority had also agreed to compare the actual revenues with its own projections of the revenue implications for the incumbent and that if at the end of the first year, the actual scenario turned out to be significantly different it would take necessary corrective measures.

2. After the notification of TTO '99, and consequent upon the announcement of New Telecom Policy (NTP) 1999 in March 1999, Secretary, Department of Telecommunication, wrote to TRAI stating, inter alia, that:

"Since the tariff order of 9th March was announced by the TRAI, there have been significant developments by way of the announcement of a New Telecom Policy yesterday which significantly alters the economics of the Telecom Sector as a whole. The new policy stipulates a shift to a Revenue Sharing arrangement with a one time Entry Fee. The policy also stipulates that TRAI recommendations will be sought by the Government on the aforesaid issue. The methodology employed and the calculations therein for calibrating tariff rates would therefore in the light of these developments undergo significant changes. While, therefore, implementing the tariff order of 9th March, 1999 for the first year, TRAI, should rework the tariff rates in the light of these developments for the subsequent period so that the new rates are in synchronisation with Government's New Telecom Policy.

3. A review by the Authority thus had to be carried out both in the light of actual situation being substantially different from that envisaged under the TTO '99 and pronouncements of a new policy by the Government, i.e. NTP 1999, which came after TTO '99 was

announced. NTP 1999 has set very ambitious teledensity targets for the country, namely, 15 per cent by 2010. It also envisages an increase in rural teledensity from 0.4 to 4 by 2010. This has necessitated a re-look on the impact of the tariff structure, on affordability, and on the consequent demand and teledensity, particularly of rural teledensity which is projected to rise to 4 per cent by 2010.

4. TTO '99 specified a standard tariff package, and allowed service providers to give alternative tariff packages together with the standard tariff package. The DTS (and MTNL) provided an alternative tariff package, under which rentals were not changed for rural subscribers, nor for urban subscribers making up to 200 metered call units (MCUs) per month. In addition, there was no reduction in the number of free calls that were provided in urban and rural areas. While this policy improved affordability of the tariffs for low callers, it also resulted in lower revenues than could have been earned if the standard tariff package were to be implemented. It is estimated that by not implementing the standard tariff package, revenues were approximately Rs.1,100 to Rs. 1,200 crores lower than the amount of revenue which could have been earned had the standard tariff package been implemented in 1999-2000.

5. The standard tariff package envisaged a decrease in STD/ISD call charge and an increase in rentals in order to re-balance tariffs and prepare the grounds for further opening up of the basic services. The change in STD/ISD call charge and rentals was considered too steep to be implemented in one step and, therefore, a three stage phase-in was specified. Most of the tariff change was to be achieved during the first two phases itself. The first phase was implemented on 1st May, 1999. The second phase was scheduled to be implemented with effect from 1st April, 2000.

6. As the end of the first phase was approaching, DTS represented to the Authority that as a result of the tariff changes, their revenues were adversely affected. In their letter dated 8th March, 2000, DTS communicated to TRAI that during the financial year 1999/2000, "the net adverse impact on the revenues of DTS may be in the range of approximately Rs.2000-2200 crores." As such DTS requested the Authority to review the TTO '99

which stipulated a further reduction in long distance charges w.e.f. 1st April, 2000 so that the DTS does not face further loss of revenue, curtailing its capability to finance further expansion programmes, particularly in loss-making urban as well as rural areas, which is considered essential to meet the teledensity targets.

7. The Authority decided to conduct a review of the tariff re-balancing exercise as envisaged at paragraphs 12 and 73 of the Explanatory Memorandum of TTO '99.

8. To conduct a review, the implementation of the second phase of tariff re-balancing exercise was deferred by a period of four months. This period had to be further extended by one month because some service providers submitted data at the end of the four-month period leaving no time for its proper analysis by the Authority. On receipt of data from service providers, TRAI has completed its tariff review, the important findings of which with respect to growth of DELs and MCUs are summarised in Tables 1, and 2 below:

Table 1. Percentage Increase In Metered Call Units (MCUs) and Direct Exchange Lines (DELs) During 1999-2000

	Projected in TTO, 1999	Actual Increase		
		DTS	MTNL	DTS and MTNL
MCUs	12.9%	10.95%	7.37%	10.2% (12% in last six months)
DELs	18%	25.36%	7.82%	22%

Source: DOT (letters dated 31st May, and 1st and 3rd August, 2000)

9. Table 1 above shows that the principal incumbent DTS was able to achieve the projected average percentage increase in DELs and the increase in MCUs was somewhat lower than that envisaged in the TTO '99. This is also valid if we consider the average achievement of DTS and MTNL together. Further, the rate of MCU increase for the last six months of the year suggests that response of STD volume to price decline will be more pronounced in the second year than in the first year of the tariff re-balancing; the increase in overall MCUs in the last four months of the financial year was 13.2 per cent.

This would indicate that with the additional time for which the first phase of tariff change has been implemented, i.e. the period beyond 31st March, 2000, the overall performance regarding DELs and MCUs has been similar to what was estimated in the TTO 1999. An important point in this context is that though the overall increase in DELs and MCUs has been close to that envisaged in the TTO '99, the increase in international call MCUs was much below expectation, even if we consider only the second half of the financial year.

10. Despite DEL and MCU growth being similar to anticipation, revenues may be lower than expected because the standard tariff package was not implemented and due to a greater than anticipated fall in average charge per call. TRAI reviewed the revenue situation on the basis of the information provided by the service providers, using the methodology that had been used by DOT for estimating revenue reduction when requesting TRAI for a review in March, 2000. With the data available at that time, DTS had anticipated a reduction in rental and call revenue of approximately Rs.2,150 crores.

11. TRAI's calculations are based on more recent data, shown in Table 2 below.

Table 2. Metered Call Units (MCUs), Call Revenue, Average Charge Per Metered Call Unit, Rental Revenue for 1998-99 and 1999-2000 for DTS and MTNL

	DTS		MTNL	
	1998-99	**1999-2000**	**1998-99**	**1999-2000**
MCUs (crores)	11,390	12,638	3,374	3,638
Call Revenue (Rs. crore)	11,180	12,280	3,704	3,717
Average charge per MCU (Rs.)	0.98	0.97	1.10	1.02
Rental revenue (Rs. crore)	2,643	3505*	887	920*

Source: DOT (letters dated 31st May, and 1st and 3rd August, 2000)

* Includes TRAI estimate of amounts for rentals relating to the year 1999-2000 collected in the year 1998-99 and taken credit for in the accounts of that year.

12. Prior to the finalization of TTO '99, DOT had provided its projection of DOT/MTNL call and rental revenues. These were without taking into account the proposed tariff re-balancing. For 1999-2000, the DOT projected these revenues to be Rs. 23,253 crore. This estimate was based on a charge of Rs. 1.243 per chargeable call, a rate which obtained in 1997-98 and which DOT expected to continue if re-balancing was not to be introduced. The projected amount was slightly adjusted by TRAI to Rs. 23,181 crore, as reported in the Explanatory Memorandum to the TTO '99. TRAI made its own estimates in respect of revenues for 1999-2000 taking into account the various changes envisaged in its proposals for tariff re-balancing. Assuming a 10 per cent volume increase in STD/ISD traffic due to tariff reduction, a situation which TRAI considered as most likely in the first year of tariff re-balancing, it estimated revenues for the year 1999-2000 to be Rs. 23,414 crore. This estimate was based on figures provided by DOT in respect of average charge per chargeable call, which they expected to obtain consequent upon the tariff re-balancing in 1999-2000. At the time of the present review, the actual call charges for the year 1998-99 (i.e. the year immediately preceding tariff re-balancing) was made available. This worked out to about Rs. 1.12 per chargeable call, i.e., lower than the call charge based on which the earlier estimate of Rs. 23,414 crore was made. A revised estimate of revenue has, therefore, been made taking the lower, and actual, call charge prevailing in 1998-99. This revised estimate amounts to about Rs. 21,870 crore. Any shortfall in revenue has to be judged from this base. As against this, the actual revenue earned in 1999-2000 amounted to Rs. 20,424 crore, resulting in a gross shortfall of about Rs. 1,450 crore. This amount includes the loss of revenue caused by not implementing the standard tariff package specified by TTO '99. Such loss of revenue to DTS/MTNL is estimated to be approximately Rs. 1,200 crore. The conclusion, therefore, is that the loss of revenue in 1999-2000 that can justifiably be ascribed to the TTO '99 is no more than Rs.250.00 crores.

13. Of the gross revenue shortfall of about Rs. 1,450 crore mentioned above, the respective shares of the incumbent operators,viz. DTS and MTNL are estimated to be Rs.600.00

crores and Rs.850.00 crores. As stated already, a substantial portion of this revenue decrease is due to non-implementation of the Standard Tariff Package.

14. The above revenue estimates have to be considered together with the declining costs of telecom equipment. This was one of the factors considered by the Authority while deciding upon the revenue effect of tariff re-balancing, as stated in paragraphs 70-71 of the Explanatory Memorandum to TTO '99. This aspect, and the service providers getting an extension of the period for the first phase of tariff re-balancing, now lead to the conclusion that the effect of the first phase of tariff re-balancing on revenue of the operators cannot be deemed to be severe. Another noteworthy point is that the Authority had expected an improvement in efficiency of the incumbent operator to also take care of some of the revenue decline occurring in the course of tariff re-balancing. Based on these considerations, the Authority is of the opinion that the decline in long-distance call revenue is not such as to warrant any further postponement of the second tranche of reduction in STD/ISD call charges envisaged in TTO '99.

15. Therefore, the Authority has decided that the proposed reduction in the STD/ISD rates for the second phase be introduced from 1st October, 2000. The Authority appreciates that a preparatory period of four weeks is required by the service providers to implement the changes in all the relevant exchanges, and to make other arrangements for effectuating the tariff changes properly.

16. Further, the Authority has decided that the second phase of STD/ISD tariffs will continue till 31st March, 2002. In all, therefore, the implementation of the entire TTO, 1999 will now extend over three years, i.e. from 1.4.99 to 31.3.2002.

17. A longer period for the second phase of tariff reduction has been permitted to enable the market to adjust to the effects of the recent policy changes in the telecom sector. Also, implementing the second phase over one- and a half years instead of one year would provide more time for the demand elasticity to manifest itself, and would give the

incumbents some additional time for structural re-adjustment in an environment where competition is increasing in all segments of the telecom service market.

18. The third phase involves a decline in STD tariffs of about 11.5 per cent from the average level of these tariffs in 1999-2000. The first two phases together achieve a reduction in STD tariff of almost 85 per cent of the total reduction that has been envisaged in the TTO '99. The Authority has taken a note of the Government's decision to open the national long distance (NLD) market for free competition and expects that the STD rates, on their own will register a significant decline due to increased competition resulting from the entry of the private sector in the NLD market. The Authority intends keeping a close watch on these developments and in line with the latest trends in telecommunication regulation, proposes to examine adoption of a market driven approach to tariff re-balancing consisting of the effect of competition on the market and its growth.

19. The second phase of tariff change included also an increase in rentals for general user subscribers, i.e. subscribers making more than 500 MCUs per month of the billing cycle. The Authority has decided not to increase these rentals, mainly for the following reasons.

(a) The additional amount of revenue that would result from the rental increase envisaged in the second phase of tariff re-balancing is about Rs. 200 crore, i.e. less than 1 per cent of the total expected revenues next year. Such a revenue loss can reasonably be expected to be more than made up through improvements in the efficiency and productivity of the incumbent operator. Also, having observed that demand is sensitive to rental or access charge, the Authority expects that not increasing rentals would spur demand and result in additional revenues. While re-balancing tariffs as a matter of policy, the Authority considers it important to achieve a good balance between cost and affordability and help build up demand for telephones in a manner which while observing the teledensity target of 15 by 2010, will endeavour to protect the financial viability of the telecom services.

(b) The Authority has permitted additional time for the first as well as the second phase of the tariff re-balancing, which in turn implies accretion of additional revenues that would more than make up for the revenue increase that could be generated by the increase of rentals in the second phase.

(c) Equipment costs have continued to decrease. If forward looking cost of only the traffic non-sensitive portion of the network is reckoned for calculating rentals then that should work as a further check on their increase.

(d) During the tariff review, the Authority has reworked cost based tariffs on the basis of a revised methodology that is mentioned in paragraph 83 of the Explanatory Memorandum to the TTO '99. This methodology and the latest forward looking cost estimates, which will be subject of consultations in the near future, would involve a review and reconsideration of some of the basis for fixing rentals and call charge. Therefore, the Authority considers it proper to defer any further increase in rental till a review of the Tariff Order along with basis of costing is undertaken in January, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054